महामहिम राष्ट्रपति जी का माननीय सदस्यों को उद्बोधन का हिन्दी रुपान्तरण

माननीय, मुझे दो भाषाएं आती है, इंग्लिश और तमिल। मैं तमिल भाषा का अच्छा वक्ता हूँ, लेकिन यहां पर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपने आप को पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ मेरे लिए नया नही है। छत्तीसगढ़ से मैं वर्षो से जुड़ा हूँ। बस्तर के जंगलों में मैं महीनों घूमा हूं, मैंने वहां के लोगों से बातचीत की है। उनकी भाषा, संस्कृति, सपने और उनके दर्द को मैं समझता हूँ। जब मैं वहां था एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहा था। उन दिनों मैं काफी कठिन परिश्रम करता था एवं रोमांचकारी गतिविधियों में संलग्न था। जगदलपुर में एक हवाई अड्डा है और वहां से हम लोग जंगलों के मध्य जाते थे। इसलिए मुझे जगदलपुर एवं बस्तर हमेशा याद आती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को नववर्ष की यद्यपि देर से शुभकामनाएं देता हूँ भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। जब भी मैं छत्तीसगढ़ के मानचित्र को देखता हूँ, मुझे दो करोड़ लोगों की याद आती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ सिंगापुर बन सकता है।

प्रतिस्पर्धा के इस युग में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का शीर्ष देश है। उसके बाद सिंगापुर जो कि एक द्वीप है, का नंबर आता है। लेकिन छत्तीसगढ़ वनों से आच्छादित खूबसूरत प्रदेश है। आपके पास विकसित राज्य बनने की सभी संभावनाएं हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास तीन

चीजें हैं। पहला छत्तीसगढ धान के कटोरे के रूप में विख्यात है, यहां उत्पादित धान की गुणवत्ता अच्छी है एवं प्रति हेक्टेयर धान की उत्पादकता अधिक है। इस कृषि उत्पाद को खाद्य प्रसंस्करण में परिवर्तित करना होगा। दूसरा यहां बहुमूल्य वन संपदा उपलब्ध है। अगर आप बांस उत्पादन में जाते हैं, तो वनवासियों के लिए आय के स्त्रोत खुलेंगे और तीसरा कोयला और विद्युत उत्पादन। आप बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में खनिजों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश में उपलब्ध जैव विविधता का उपयोग औषधि खेती में किया जा सकता है। औषधियों के मूल्य संवर्धन के लिए इसका उपयोग दवाईयों में किया जा सकता है।

मित्रों, इस परिचय के साथ मेरे पास पन्द्रह मिनट का समय है। मैं विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़, नेता प्रतिपक्ष एवं विधानसभा के सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे पास 2020 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य है। देश की 26 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करती है, इन लोगों का विकास जरूरी है। जब हम छत्तीसगढ़ की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि वनवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रदेश की आबादी का 50 प्रतिशत है। इन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। यह कैसे होगा ? राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास एक योजना है, वर्तमान में हमारा सकल घरेलू उत्पाद 6 प्रतिशत है यद्यपि इसे 8 प्रतिशत कहा जाता है। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर हमारा सकल घरेलू उत्पाद 10 प्रतिशत होता है एवं इस दर को हम 10 वर्षो तक कायम रख पाते हैं, तो गरीबी रेखा से नीचे निवासरत 26 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर ला सकते हैं।

यह कैसे संभव होगा ? इसके लिए हमारे पास क्या–क्या साधन है ? सूचना प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा गठित टीम ने 5 क्षेत्रों को चिन्हित किया है। पहला शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य को जान बूझकर संबद्ध किया गया हैं। उसके बाद कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी।

(महामहिम राष्ट्रपतिजी के सम्बोधन के समय आसन में अस्थायी परिवर्तन)

मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सन् 1857 में देशवासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरूआत की। 1857 से 1947 तक 90 वर्षो का लम्बा समय, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के वीरनारायण सिंह के द्वारा किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन्हें याद करते होंगे, या आप लोगों ने उन्हें भूला दिया ?ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर 10 दिसम्बर 1857 में फांसी दी। वे स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद और छत्तीसगढ़ के सम्मान के प्रतीक हैं। आज के दौर में उनके जैसा व्यक्तित्व मिलना मुश्किल हैं। मैं विधानसभा के लोगों को सुझाव देना चाहता हूँ कि उनकी याद में आप स्मारक जरूर बनाएं, आप कुछ ऐसा करें कि शहीद वीरनारायण सिंह चिरस्थायी रूप से हमारे स्मृति पटल में बसे रहें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ?आप सौ बिस्तरों वाला हॉस्पिटल बना सकते हैं। यह हॉस्पिटल बस्तर में हो सकता है या आप बस्तर की चारों तरफ वीरनारायण सिंह जी के नाम पर रेल लाईन बिछा सकते हैं, या उनके नाम पर 10वीं कक्षा तक स्कूलों की श्रृंखला खोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के उस महान सपूत के विषय में मैं यही बताना चाह रहा था।

मैने संसद में 6 से 14 आयु समूह के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित 'शिक्षा का अधिकार' विधेयक को स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ इस

विधेयक को मिशन के रूप में अपनाने वाला पहला प्रदेश होना चाहिए। विशेषकर महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। इसे 40–45 प्रतिशत से आगे बढ़ाना होगा। महिला शिक्षा सशक्तीकरण से दो बातें होंगी। एक परिवार छोटा होगा। दूसरा संयुक्त परिवार व्यवस्था का विकास होगा।

(महामहिम राष्ट्रपतिजी के सम्बोधन के समय आसन में अस्थायी परिवर्तन)

अब मैं पुनः विकासशील भारत की बात पर आता हूँ। मैं इस विधायिका से एक और महत्वपूर्ण यह बात कहना चाहता हूं कि सन् 1947 के स्वतंत्रता संग्राम से न केवल हमें आजादी मिली, बल्कि 19वीं शताब्दी के उस आंदोलन ने हमें अच्छे नेता दिए। क्या आपको अंदाज है कि आजादी से हमें क्या–क्या मिला ? आप सभी को मालूम है कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए। छत्तीसगढ़ स्वयं धान के उत्पादन में काफी आगे है। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने की वजह से लोगों के जीवन–स्तर में सुधार हुआ है, विशेषकर मध्यमवर्गीय परिवारों के जीवन–स्तर में सुधार हुआ है।

अब राष्ट्र के सामने दूसरा लक्ष्य है कि सकल घरेलू उत्पाद की आर्थिक विकास दर 10 प्रतिशत एवं गरीबी स्तर को 0 प्रतिशत पर लाएं। हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना होगा तभी हम विकसित भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं। सन् 2003 में सकल घरेलू उत्पाद 8.4 प्रतिशत मापा गया, जबकि हम इसे 6 प्रतिशत मानते हैं, चूंकि हमारी स्थिति अन्य देशों से अच्छी नहीं है। इसलिए भारत के विकास के लिए समन्वित प्रयास करना होगा। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6 प्रतिशत है और गरीबी रेखा से नीचे

26 प्रतिशत लोग निवासरत हैं। हमारा उद्देश्य देश से गरीबी को हटाना है इसके लिए हमे सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर 10 प्रतिशत करना होगा तभी हम 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला सकेंगे। यह कैसे संभव है ?

इसके लिए 500 सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने 5 क्षेत्रों को चिन्हित किया है। सर्वप्रथम कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण – जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप धान, सब्जी एवं फलों का उत्पादन करते हैं लेकिन इसके मूल्य संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण अपनाना होगा तभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं खाद्य प्रसंस्करण का विकास होगा। दूसरा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का संबंध। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के परिणामस्वरूप रोजगार, खाद्य सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मूल्य संवर्धन होगा। यदि इसे मिशन के रूप में लागू किया जाता है तो इसके परिणाम की आप कल्पना नही कर सकते। तीसरा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो छत्तीसगढ़ के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से रोजगार के अवसरों के साथ ही साथ निर्यात के माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र लाभान्वित होगा। विशेषकर टेलीमेडिसीन, टेलीएजुकेशन और ई–गर्वनेंस से। इन तीनों के समन्वय से आप दूर–दराज के गांवों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में निवासरत लोगों को भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी – महानदी है। हर साल उत्तर–पूर्वी राज्यों में ब्रम्हपुत्र नदी की वजह से बाढ़ आती है जबकि मध्य भारत एवं दक्षिण

भारत और कभी–कभी गुजरात में सूखा का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में नदियों को जोड़ने के उद्देश्य से कार्ययोजना बनाने के लिए एक टॉस्कफोर्स का गठन किया है। इस योजना के तहत देश के उच्च क्षेत्र वाली ऐसी नदियों को जिसमें जल की अधिकता रहती हैं उन्हें कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। मैं इन दो मिनटों में इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद महत्वपूर्ण तकनीक एवं सामरिक उद्योगों पर चर्चा करूंगा। आपको याद होगा सन् 1998 में जब भारत आणविक शक्ति बना था, तो विकसित देशों ने भारत पर आर्थिक एवं तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे। हम इस स्थिति से बचना चाहते हैं। इसलिए हमें महत्वपूर्ण तकनीक एवं सामरिक उद्योगों के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें इन पांच क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इन पांच क्षेत्रों की आत्म निर्भरता से ही हम भारत वर्ष को 2020 तक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। अब आर्थिक विकास की मुद्दे पर आता हूँ। अगर हम छत्तीसगढ़ का उदाहरण लेते हैं तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत की आबादी 120 करोड़ है और छत्तीसगढ़ की आबादी 2.7 करोड़ है। यहां का लिंग अनुपात 990 जो कि काफी अच्छा है। महिला साक्षरता दर 52.40 प्रतिशत है एवं छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में यह दर 40 से 42 प्रतिशत है।

हमारे अध्ययन के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 36 प्रतिशत आबादी को स्वच्छ पानी, शौचालय एवं बिजली की सुविधाएं उपलब्ध नही है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे निवासरत लोगों की संख्या 42 प्रतिशत है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 38 प्रतिशत है। हमें इनके आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करना होगा एवं इन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। आज मैं जब माननीय मुख्यमंत्रीजी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मंशा है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो। महिला साक्षरता पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है एवं कृषि को एक फसलीय से दो फसलीय में परिवर्तित करना होगा। गेहूं एवं धान की खेती के बीच चार महीनों का समय होता है, यह समय औषधीय खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। औषधीय खेती से प्रति हेक्टेयर 60 से 80 हजार रूपए का मुनाफा होता है। आप तिलहन पौधों एवं अन्य नगदी फसलों की खेती कर सकते हैं। इन फसलों पर आधारित उद्योगों की स्थापना जरूरी है। वन क्षेत्र में लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा एक अच्छी नीति है एवं सामाजिक वानिकी

जरूरी है। बांस का रोपण जो आप कर रहे हैं एक अच्छा प्रयास है। बांस लकड़ी का उत्पादन अल्प समय में किया जा सकता है। आप इसे काट सकते हैं एवं पुनः रोपित कर सकते हैं। काष्ठ उत्पादन का उपयोग भवन निर्माण एवं काष्ठ शिल्पों में भी किया जा सकता है। इन सभी कार्यो के लिए आपको एक विशेष वर्ग के समूह तैयार करना होगा। अगर आप सामाजिक वानिकी को नहीं अपनाते हैं, तो आपकी वन संपदा अनुपयोगी हो जाएगी ।

अगला बिन्दु है – खनिज संसाधन। आप सभी इससे वाकिफ है और बहुत से खनिज बहुलता वाले क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हैं। उच्च श्रेणी का लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जा रहा है, यह मुझे पसंद नही है। निर्यात से आपको कुछ हजार डॉलर की प्राप्ति होती है, जबकि आप इसका मूल्य संवर्धन अपने देश में कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अगर 100 प्रतिशत लौह अयस्क का उपयोग स्टील उत्पादन में अपने देश में किया जाता है तो देश के राजस्व में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ भारत में टिन उत्पादन करने वाला अकेला प्रदेश है। इसके मूल्य सर्वद्धन के लिए टिन आधारित उत्पादों पर ध्यान देना होगा। अद्योसरंचना के क्षेत्र में शेष 10 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण समयबद्ध तरीके से होना जरूरी है। सड़कों का निर्माण विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो रेल्वे की सुविधा से वंचित है वहां जरूरी है। मैं सोचता हूं कि बस्तर के विकास के लिए कुछ आदिवासी बाहुल्य जिलों में सरकुलर ट्रेन सुविधाएँ अधिक उपयुक्त होंगी।

नदियों को जोड़ने के योजना के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि इससे 25 प्रतिशत अतिरिक्त कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 35 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा, बाढ़ एवं सूखा पर नियंत्रण होगा, तत्पश्चात् पेयजल की उपलब्धता, पर्यावरण में सुधार एवं रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इससे न सिर्फ नदियां जुड़ेगीं बल्कि निश्चित रूप से भारत का एकीकरण होगा। अन्य नदियों की तुलना में महानदी का उद्गम और उसका अधिकांश हिस्सा आपके राज्य की सीमाओं में होने से इसका अधिकाधिक लाभ राज्य को होगा।

अब मैं माननीय सदस्यों से एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा करना चाहता हूँ – 70 करोड़ जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। भारत में 6 लाख गांव है और इन 6 लाख गांवों में 70 करोड़ जनता निवासरत है। अगर हम इनका विकास चाहते हैं तो हमें इन्हें शहरी क्षेत्रों से जोड़ना पड़ेगा इसे हम 'पूरा प्रोजेक्ट' के द्वारा कर सकते हैं। 'पूरा' का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। सरकार ने भी इस योजना को स्वीकार कर लिया है एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। निश्चय ही छत्तीसगढ़ में 'पूरा' योजना के लिए बेहतर संभावनाएं है। अगर हम बस्तर को लेते हैं तो बस्तर में 20–30 गांव हैं। इन 20–30 गांव की आबादी लगभग दस हजार होगी और अगर हम 40 गांवों को लेते हैं तो इनकी आबादी 20 हजार होगी। इन गांवों को सड़कों से जोड़ते हैं तो यहां पर यातायात का विकास होगा। यही केन्द्र सरकार की योजना है। केन्द्र सरकार सड़क एवं यातायात सुविधा मुहैया कराना चाहती है लेकिन सड़को के लिए भूमि का अधिग्रहण एक बड़ी समस्या है। हम रिंग रोड का विकास करते हैं तो यातायात को सुगम बना सकते हैं। इसके साथ रेल्वे के माध्यम से लोगों को आवागमन की सुविधाएं, स्कूलों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंच बनती है एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है।

हम इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से संवाद एवं संपर्क स्थापित कर सकते हैं इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर राजधानी से गांवों तक बिछाया जा सकता है। कुछ स्थानों पर सेटेलाईट, वायरलेस और फाइबर केबल के माध्यम से संवाद स्थापित किया जा सकता है। इससे टेलीमेडिसीन, टेलीएजूकेशन और पब्लिक कॉल आफिसेस, ग्रामीण इंटरनेट ढाबा जैसी महत्वपूर्ण चीजों की सुविधाएं मिल सकती हैं, याने कि 'पूरा' ग्रामों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में भौतिक संपर्क एवं इलेक्ट्रानिक संपर्क की सुविधाएँ विकसित होंगी।

तीसरा संपर्क है ज्ञान के संचार का – आपके पास स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। उदाहरण के लिए आपकी छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ हिस्सों में वन क्षेत्र, कुछ में खनिज, हस्तशिल्प है। इन क्षेत्रों के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि श्रमिक प्रशिक्षण केन्द्र, स्कूल, हॉस्पिटल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को ज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों के आपस में जुड़ने से गांव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर केन्द्र के रूप में उभरेंगे। आर्थिक गतिशीलता से छोटे–छोटे उद्योगों का विकास होगा विशेषकर कृषि उद्योग और इसकी वजह से वेयर हॉउस, लघु तापघर, अक्षय ऊर्जा, उद्यमिता, रोजगार अवसर, ग्रामीण बाजारों का विकास होगा एवं गांवों में आर्थिक गतिविधियों का सूत्रपात होगा। ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए 'पूरा' एक तकनीकी चुनौती का कार्य है। "पूरा"का प्रबंधन निजी हाथों में होना चाहिए। क्योंकि इसके माध्यम से स्कूल, हॉस्पिटल, छोटे ताप घर सड़क और संचार केन्द्रों का संचालन होना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे नागरिकों में जागरूकता, व्यक्तित्व एवं नेतृत्व क्षमता में नैतिकता का विकास होगा। 10–15 ग्रामों के समूह बनाकर विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सुनियोजित योजना बनाकर जिसे बढ़ाकर 25 गावों का समूह बनाया जा सकता है। आबादी और लागत की आवश्यकता के अनुरूप 100 करोड़ तक निवेश कर लगभग 3000 से 5000 तक के व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकेगा तथा इससे रोजगार के अवसर बढ़ेगा। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

महामहिम राष्ट्रपतिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से माननीय सदस्यों को विजन 2020 के बारे में जानकारी देते हुए ।

मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों में सृजनात्मक क्षमताओं का विकास जरूरी है। एक दूरदर्शी नेता कौन होता है ?एक दूरदर्शी नेता अपने नेतृत्व क्षमता से कमांडर की भूमिका को कोच के रूप में परिवर्तित करता है। एक सृजनात्मक नेता कमांडर के बजाए कोच की भूमिका अदा करता है। वह एक प्रबंधक के बजाए शिल्पकार, निदेशक के बजाए अधिकारों के हस्तांतरण के माध्यम से कार्य करता है। संक्षेप में वह सम्मान मांगने के बजाए सम्मान का कारण बनता है।

इन सभी बातों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ, आप पूछ सकते हैं कि इन सभी के लिए पैसा कहां से आएगा। हमारे पास किस तरह की अधोसंरचना उपलब्ध है ? हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, देश का तीन छोर समुद्री तट से घिरा है, खनिज संसाधन, जैव विविधता एवं मानव संसाधन के मामले में हम धनी है। हमें इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एवं मूल्य संर्वधन करना है। आप इसे कैसे करेंगे ? आप मूल्यवर्धन, प्रौद्योगिकी केन्द्रों एवं ज्ञान और उत्पादकों के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्नॉलॉजी मिशन 2020, इस मिशन से खाद्य स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक संपन्नता, आंतरिक एवं सामाजिक सुरक्षा मिलेगा और अंततः इसके माध्यम से वर्ष 2020 तक विकसित भारत का निर्माण होगा। इससे भारत विश्व में अधिकारपूर्वक अपना गरिमामय स्थान प्राप्त कर सकेगा। मित्रों मैं यही सब कहना चाहता हूँ आप किसी भी भाषा में कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। **नहीं** तो मैं प्रश्न **करूँगा**, मैं तैयार **हूँ।**